

अध्याय – 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये सवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरणों को आवंटित बजट

आदरणीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपमहापौर महोदय, लोकप्रिय सभासदगण, निगम अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं जयपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं। आप सभी का जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हार्दिक अभिनन्दन एवं हार्दिक स्वागत।

सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जयपुर नगर निगम के पांचवें बोर्ड की साधारण सभा की दूसरी बैठक में मुझे आप सभी के समक्ष वर्ष 2010–11 के आय व्ययक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

साथियों, वर्ष 2010–11 का बजट जयपुर शहर को वर्ल्डक्लास सिटी बनाये जाने के क्रम में बहुमंजिला पार्किंग स्थलों के विकास एवं आपदा प्रबन्धन कार्यों को समर्पित करते हैं।

जयपुर शहर गौरवशाली विरासत के लिये विश्व भर में पहचान रखने वाला शहर है जो अब अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करने वाले शहर के रूप में उभर कर आ रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में आधुनिक युग के विकास, सुविधाएं एवं तकनीक अपनाने में जयपुर शहर देश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण एशिया में अग्रणी शहर बन गया है।

जयपुर को विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान करने तथा परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर जयपुर शहर के लिए वर्ष 2031 तक जन-आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान' की डी.पी.आर. बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य शहर में उपलब्ध भूमि के अनुसार बेहतर परिवहन सुविधाओं का विस्तार तथा जनता को वाजिब दरों पर द्रुतगामी आधुनिक बस सेवा और मैट्रो रेल संचालन को सुचारू किया जाना है। इसी क्रम में बी.आर.टी.एस., मैट्रो रेल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली गई है तथा मोनो रेल प्रोजेक्ट पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम द्वारा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन स्थल के आसपास मूलभूत सुविधाएं जुटानें जैसे पार्किंग स्थलों का विकास, जनसुविधाओं का निर्माण, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, आदि का कार्य किया जायेगा। जयपुर शहर में यातायात सुधार के लिये अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में टोंक रोड पर दो राज्य के पहले एस्केलेटर (अत्याधुनिक फुटब्रिज) का निर्माण नारायण सिंह सर्किल एवं टोंक पुलिया पर बी.ओ.टी. आधार पर करवाया गया है।

शहर में बढ़ती वाहनों की रेलमपेल को देखते हुए शहर में दो स्थानों बाईस गोदाम तथा गुर्जर की थड़ी पर अण्डर बाईपास बनाने की योजनाएं शीघ्र मूर्त रूप लेंगी। महेश नगर, कतारपुरा तथा आस-पास की सघन कॉलोनियों के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर अण्डर बाईपास बनाये जाने की योजना शीघ्र प्रारम्भ होगी। इनके निर्माण से आस-पास की कॉलोनियों के निवासियों को राहत मिलेगी। शहर में द्रुतगति की यातायात व्यवस्था को संचालित करने के लिये जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युवल मिशन परियोजना के तहत बी.आर.टी.एस. का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के पैकेज-1 बी के तहत सीकर रोड पर 7.1 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा दुर्गापुरा पर ऐलीवेटेड रोड का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तहत शहर में 45 मीटर चौड़ी सड़क पर 400 लो फ्लोर बसों का संचालन किया जायेगा।

साथियों, हम जयपुर को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर शहर में आधुनिक जन-सुविधाओं और संसाधनों का विकास हो यह हमारी प्राथमिकता है। आने वाले समय में जयपुर उत्तर भारत का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर पार्किंग सुविधाएं एवं आवागमन के साधन विश्वस्तरीय होंगे।

जयपुर नगर निगम ने शहर के यातायात सुधार एवं सुव्यवस्थित पार्किंग योजनाओं को विकसित कर आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से शहर में 7 स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग परियोजना ‘पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप’ आधार पर बनाने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में शहर में 3 स्थानों पर रामलीला मैदान, रंगमंच एवं अशोक मार्ग सी-स्कीम तथा मॉल-21 के पीछे अत्यधिक बहुमंजिला पार्किंग परियोजनायें विकसित की जायेंगी। द्वितीय चरण में चांदपोल अनाज मण्डी, आतिश मार्केट, सिंहद्वार के पास तथा गवर्नमेन्ट हॉस्टल के पास बहुमंजिला पार्किंग परियोजनायें बनाई जायेंगी। गवर्नमेन्ट हॉस्टल के पास मैट्रो रेल आने के कारण उक्त स्थल पर बनाई जाने वाली पार्किंग योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

शहर में बनायी जाने वाली बहुमंजिला पार्किंग परियोजनाओं से 5400 ईसीएस (चौपहिया वाहन) पार्किंग विकसित होगी। पहले चरण में 160 करोड़ की लागत से बनायी जाने वाली पार्किंग परियोजना से 3000 ईसीइस (चौपहिया) पार्किंग विकसित होगी। आने वाले समय में यह परियोजना देश के अन्य शहरों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगी। जयपुर नगर निगम की तर्ज पर ही जयपुर विकास प्राधिकरण भी रामनिवास बाग में 1600 कारों के लिये भूमिगत पार्किंग परियोजना को शीघ्र ही कार्यरूप में परिवर्तित करेगा।

साथियों, शहर के यातायात को बेहतर सुविधाजनक एवं द्रुतगामी बनाये जाने की दृष्टि से शहर में खासाकोठी पर फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर मल्टी लेविल फ्लाईओवर निर्माणाधीन है।

जयपुर शहर को आगरा रोड से जोड़ने वाली घाट की गूणी के संकड़े रास्ते पर भारी यातायात के दबाव तथा आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के स्थायी समाधान के साथ गूणी में स्थित पुरा सम्पदाओं को श्रय होने से बचाया जा सके और जयपुर में पूर्व दिशा में अवरुद्ध पड़े विकास को गति मिल सके इसके लिये घाट की गूणी टनल परियोजना का शिलान्यास 13 अक्टूबर 2009 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। उक्त परियोजना प्रगति पर है।

मित्रों, नियोजित जयपुर शहर बढ़ती जनसंख्या के कारण अब सिकुड़ता जा रहा है। जयपुर शहर की समृद्धि एवं विकास ने सदैव यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया है एवं उन्हें इस शातिप्रिय, वैभवशाली शहर में बसने के लिये आमंत्रित किया है। जिसके फलस्वरूप मात्र 2 लाख लोगों के निवास के लिये बसाये गये हैरिटेज सिटी जयपुर में आज 30 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए राज्य सरकार ने शहर के साथ-साथ सैटेलाइट कस्बों एवं निकट के गांवों के समुचित विकास की योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया है। जिससे शहर में बढ़ती आबादी के दबाव को कम किया जा सके। साथ ही आस-पास के गांवों में रोजगारोन्मुखी विकास संभव हो सके। नया जयपुर शहर योजना इस ओर एक प्रयास है।

सभासदों, जयपुर नगर निगम का सैद्धान्तिक कार्य शहर की सफाई व्यवस्था एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने का है।

मैंने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि किस प्रकार हम सभी जन-सहयोग से शहर को स्वच्छ, सुंदर,

हरा—भरा बनायें। सफाई व्यवस्था एक ऐसा विषय है जो हमेशा अधूरा रहा है। इस ओर बहुत कुछ किया जाना शेष है।

साथियों, शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के लिये सफाई व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया गया है जिससे सफाई कर्मचारी से लेकर आयुक्त तक हर व्यक्ति को सफाई व्यवस्था के लिये जिम्मेदार बनाया जायेगा। इसी कड़ी में यह निर्णय भी लिया गया है कि सफाई कर्मचारियों की बीटों का पुर्ननिर्धारण किया जाये। जिससे हर कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्व की पालना समय से कर आम नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रख सके।

शहर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था के कार्यों को निजी क्षेत्र से जोड़ा जाये। गत अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए चारदीवारी के भीतर एवं बाहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए यह कार्य सक्षम संविदाकारों द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

मित्रों, शहर की सफाई व्यवस्था में जनभागीदारी की प्रमुख भूमिका है। पूर्व में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने की योजना शहर में विभिन्न स्थानों पर चलायी गयी थी। योजना में जनभागीदारी एवं जागरूकता के अभाव के कारण आम नागरिकों की उदासीनता रही जिसके फलस्वरूप योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं नहीं हो सका। मेरा यह प्रयास रहेगा कि शहर की सफाई व्यवस्था में शहर का पहला कचरा उत्पादक किसी भी पारिवारिक इकाई का बच्चा शहर की सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्ण जागरूक हो।

इसके लिये शहर में “स्वच्छता जागरूकता अभियान” चलाया जायेगा तथा अभियान से सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों को जोड़ा जायेगा। इससे हर घर में एक सदस्य स्वच्छता प्रतिनिधि के रूप में तैयार होगा एवं सम्पूर्ण परिवार सफाई व्यवस्था से जुड़ सकेगा।

विश्व की ज्वलन्तम समस्याओं में ठोस कचरा प्रबन्धन प्रमुख समस्या है। केन्द्र की प्रवर्तित योजना जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युवल मिशन के तहत 13.19 करोड़ रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सुधार कार्यक्रम शहर में चलाया जा रहा है। योजना के तहत सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण करते हुए इसका पूर्ण रूप से यांत्रिकीकरण किया जा रहा है। योजना के तहत शीघ्र ही 250 मैट्रिक टन क्षमता का कम्पोस्ट प्लान्ट (खाद बनाने का संयंत्र) सेवापुरा में लगाया जा रहा है।

शहर की सफाई व्यवस्था में समयबद्धता पहली आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी है कि सफाई कर्मचारी एवं जिनकी देखरेख में सफाई होती है वे निर्धारित कार्यस्थल पर समय पर पहुँचे तथा अपने कार्यों को पूर्ण दायित्व के साथ पूरा करें। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने के लिए शीघ्र ही बायोमैट्रिक्स मशीनें सभी हाजरीगाहों पर लगायी जायेंगी।

यह व्यवस्था निगम के अन्य कर्मचारियों पर भी लागू की जायेगी तथा बायोमैट्रिक्स मशीनें सभी जोनल एवं मुख्यालय कार्यालय में लगायी जायेंगी। शहर में पूर्व में कचरे से पैलेट्स बनाये जाने का प्लान्ट 20 करोड़ की लागत से बी.ओ.टी. आधार पर लगाया जा चुका है शीघ्र ही शहर में कचरे से ऊर्जा बनाये जाने का संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। उक्त संयंत्र को लगाये जाने के लिये भूमि का चिन्हीकरण किया जा रहा है।

मित्रों, कार्यों में पारदर्शिता होती है तो कार्य निर्धारित समय में पूरे होते हैं। शहर में सफाई व्यवस्था के दौरान कचरा परिवहन कार्य निजी क्षेत्र में दिया हुआ है ऐसे में कचरा **तुलाई केन्द्रों** पर

पारदर्शिता रखने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने प्रस्तावित हैं। इस योजना के लागू होने से कचरा परिवहन के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता आयेगी। कार्मिकों के उत्साहवर्धन के माध्यम से उन्हें अधिक कार्य कुशल बनाया जा सकता है।

स्ट्रीट वैण्डर –

साथियो! जयपुर नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थित रूप से कार्य करने वाले लघु व्यापारियों (स्ट्रीट वैण्डर) का सर्वे कर पंजीयन करने एवं उन्हें परिचय पत्र देने का निर्णय लिया है। स्ट्रीट वैण्डर्स को नगर निगम बैंक के माध्यम से ऋण दिलवायेगा तथा उन्हें रियायती दरों पर व्यवसाय करने के लिए ठेला भी उपलब्ध करवायेगा। निगम द्वारा स्ट्रीट वैण्डर्स को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाये इसके लिए व्यापक सर्वे सभी जोनल कार्यालयों के माध्यम से करवाया जा रहा है। निगम द्वारा सभी स्ट्रीट वैण्डरों का स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ चैकअप) करवाया जायेगा एवं उनका बीमा भी करवाया जायेगा।

निजी चिकित्सालयों का पंजीयन–

जयपुर शहर के बढ़ते क्षेत्रफल को देखते हुए शहर के हर क्षेत्र में निजी चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में आवश्यक है कि शहर के सभी निजी चिकित्सालयों को पंजीयन निगम द्वारा किया जाये। जिससे निजी चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं पर अंकुश रहेगा एवं पंजीयन से निगम को राजस्व प्राप्ति हो सकेगी।

सफाई कर्मचारी कल्याणकारी योजनाएं –

साथियो! सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की पदोन्नति के कार्य एवं मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति तुरंत प्राप्त हो सके इसके लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे एवं आयुक्त कार्मिकों को इसके लिये उत्तरदायी बनाया जायेगा। कार्यों के दौरान सफाई कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क कैप, गम्बूट उपलब्ध हों इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का कार्य प्रशासन शहरों के संग अभियान में किया गया है। भविष्य में सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण साल में दो बार हो सके इसके लिये सभी जोनल आयुक्त व स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

जयपुर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के हितार्थ उनका सामूहिक बीमा करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2009–10 की वर्दी दी जा चुकी है। सफाई कर्मचारियों को शीघ्र ही परिचय पत्र दिये जाने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

शहर की बढ़ती आबादी एवं क्षेत्रफल के मददे नजर शहर में सफाई कर्मचारियों की कमी है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 500 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्य जारी है शीघ्र ही शहर में पुर्नबीट निर्धारण से सफाई कर्मचारी अधिशेष होंगे ऐसी स्थिति में अनमेन्ड क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी लगाये जा सकेंगे। यदि फिर भी आवश्यकता हुई तो आवश्यकतानुसार अस्थाई सफाई कर्मचारी सम्बन्धित वार्डों में लगाये जायेंगे।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 158 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था

अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना हमारी कार्य पद्धति का प्रमुख अंग है। शहर के 77 वार्डों के कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था को बनाये रखना जयपुर नगर निगम का प्रमुख कार्य है। हम इस कार्य को पूर्ण प्रतिबद्धता से कर रहे हैं। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं तथा सभी सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था शिकायत केन्द्रों पर शिकायतों का तुरन्त निस्तारण हो सके इसके लिए टोल फ्री दूरभाष नम्बरों की व्यवस्था की जा

रही है। यह व्यवस्था शहर के सभी हैल्प लाईन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से आम नागरिक सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी अपनी शिकायतों को निःशुल्क दर्ज करवा सकेगा।

साथियों, शहर के 77 वार्डों में लगभग डेढ़ लाख पोल पर जयपुर नगर निगम द्वारा लाईटें लगाई गई हैं। प्रत्येक पोल पर लगी सोडियम/ट्यूबलाइटों की जानकारी एक समय में एक साथ प्राप्त हो सके इसके लिये सभी वार्डों में स्थित लाईट पोल का डिजीटल सर्वे करवाया जायेगा। जिससे शहर में लाइटों की स्थिति का पता चल सकेगा तथा एवं बन्द लाइटों को तुरन्त ठीक करवाया जा सकेगा। इससे आम नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

ए.ई.डी. टैक्नोलॉजी लाईटें –

जयपुर शहर में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था पर प्रति माह विद्युत व्यय के रूप में 125 लाख रुपए व्यय होते हैं। इस ओर कभी भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार इस मद में होने वाले व्यय में कमी की जाये एवं परम्परागत ऊर्जा को बचाया जाये। पहली बार इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं जयपुर शहर की सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में स्थाई सुधार/निराकरण के लिए सम्पूर्ण जयपुर में चरणबद्ध तरीके से स्विस चैलेंज एप्रोच सिद्धान्त पर आधारित एल.ई.डी. टैक्नोलॉजी की लाईटें लगाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लाइटों का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था जो सफल रहा है। एल.ई.डी. टैक्नोलॉजी की लाईटें मैन्टीनेन्स फ्री लाइट सिस्टम हैं। इसके अतिरिक्त एल.ई.डी. लाईटें ग्रीन लाईटें होने से प्रदूषण मुक्त हैं। इन लाईटों के लगाने से निगम को कार्बन क्रेडिट का भी लाभ प्राप्त होगा जिससे विशेष आय प्राप्त होगी एवं विद्युत अपव्यय में 60 प्रतिशत की बचत होगी। जिससे उक्त लाइटें लगाई जा सकेंगी। एल.ई.डी. टैक्नोलॉजी की लाईटें प्रथम चरण में स्टेच्यू सर्किल से चारों ओर जाने वाले रास्तों पर लगायी जायेंगी तथा इसके पश्चात् चारदीवारी में लगाये जाने वाले हैरिटेज पोल पर छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ एवं सुभाष चौक तक लगायी जानी प्रस्तावित हैं।

जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण की दृष्टि से सम्पूर्ण शहर में जहां विद्युत लाइटों को भूमिगत किया जा रहा है वहां पर हैरिटेज लुक के पोल लगाये जायेंगे तथा शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों पर आवश्यकतानुसार हाईमास्ट लाइटें लगायी जायेंगी। वर्तमान में शहर के 729 उद्यानों का रखरखाव जयपुर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इन उद्यानों में से 129 उद्यान जयपुर विकास प्राधिकरण से हाल ही में हस्तान्तरित होकर आये हैं। शहर के कुछ उद्यानों में पूर्व में भी विद्युत व्यवस्था सोलर लाइटों के माध्यम से की गई थी। उक्त प्रयोग की सफलता को देखते हुए शहर में स्थित सभी उद्यानों में सोलर लाइटें लगाया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य को विज्ञापन दाताओं द्वारा करवाये जाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। इससे जहां एक ओर पारम्परिक ऊर्जा की बचत होगी वहीं दूसरी ओर निगम का विद्युत व्यय भी कम होगा तथा सोलर लाइटें लगाने का व्यय भार भी निगम को वहन नहीं करना पड़ेगा। शहर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में नये क्षेत्रों में लाइटें लगाये जाने एवं व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2010–11 में 8000 सोडियम एवं 25000 ट्यूबलाइटें क्रय की जानी प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 3800 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

अग्निशमन व्यवस्था

जयपुर शहर के वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ते कदमों को देखते हुए शहर में विभिन्न औद्योगिक घरानों, मल्टीनेशनल कम्पनियों ने अपने कार्यालय यहां खोले हैं। शहर धीरे-धीरे महानगर बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में शहर में बड़े मॉल, बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसरों व आवासों का निर्माण हो रहा है। विकास की बढ़ती दर को देखते हुए यहां बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के जीवन की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध की जिम्मेदारी जयपुर नगर निगम की है।

स्नॉर्गल लैडर एवं क्रेश फॉम टैण्डर—

जयपुर नगर निगम ने नागरिक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है एवं अग्निशमन से जुड़ी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है इसी क्रम में राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के पहले एक ए.एच.एल.पी. (एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म) 42 मीटर की ऊंचाई का बचाव कार्य एवं आग बुझाने के लिये क्रय किया जा रहा है। इसका कार्यादेश दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त छोटी गलियों में जहां बड़े अग्निशमन वाहनों का जाना संभव नहीं है उनके लिए 7 नग छोटे अग्निशमन वाहन क्रय किये जा रहे हैं तथा 8 और छोटे अग्निशमन वाहन बनवाए जा रहे हैं।

सीतापुरा में आई.ओ.सी. डिपो में हुए अग्निकांड को देखते हुए राज्य सरकार के सहयोग से तेल की आग बुझाने के लिए 1.75 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में पहली बार एक “क्रैश फॉम टैण्डर” क्रय किया जा रहा है। साथ ही 10 नग वाटर वाऊजर फोम टैण्डर तथा तेल की आग बुझाने के अग्निशमन वाहन क्रय किये जा रहे हैं। शहर में रीको के सहयोग से मालवीय नगर, बिन्दायका, बगरू, झोटवाडा, हीरावाला औद्योगिक क्षेत्रों में नये अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के लिये रीको भूमि, भवन, अग्निशमन वाहन उपलब्ध करायेगा। निगम द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से अग्निशम सेवाओं का पूर्ण आधुनिकीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 2000 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

सीवर परियोजना

जयपुर सीवरेज प्रोजेक्ट फेज द्वितीय राशि 110.86 करोड़ रुपए की भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत ट्रांसपोर्ट नगर से रामगढ़ मोड़ तक 13.266 करोड़ रुपए की राशि से सीवर नेटवर्क का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की 52000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

जयसिंहपुरा खोर में 50 एम.एल.डी. क्षमता का ट्रीटमेन्ट प्लांट शहर के उत्तरी क्षेत्र में आने वाले सीवरेज के लिये 23.175 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है।

डेलावास (प्रताप नगर) में 62.50 एम.एल.डी. क्षमता का ट्रीटमेन्ट प्लांट शहर के दक्षिणी क्षेत्र से आने वाले सीवरेज के लिये 28.963 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है।

डेलावास में ही 62.50 एम.एल.डी. इकाई प्रथम की उत्पादित बायो गैस 0.5 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से उत्पादित विद्युत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट को चलाने के काम में आयेगी। इससे प्रति माह निगम के राजस्व में 12–13 लाख रुपए की बचत हो सकेगी।

जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को सीवरेज से जोड़ने के कार्य ‘प्रॉपर्टी कनैक्शन’ का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर 37.728 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। योजना की पुर्णसमीक्षा की जाकर इसकी सभी खामियों को दूर किया जा रहा है।

मित्रों, जयपुर नगर निगम शहर के निचले क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों में सीवर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीवर लाईन डालने व छोटे एस.टी.पी. 0.5 एम.एल.डी. क्षमता से लेकर 10 एम.एल.डी. क्षमता तक लगाने की योजना बना रहा है। इस योजना की क्रियान्विति से शहर के निचले क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों में भी सीवर लाईनें डाली जाकर सीवरेज जल का वहीं निस्तारण किया जा सकेगा।

सीवरेज क्षेत्र में दूसरी बड़ी प्रस्तावित परियोजना 20 एम.एल.डी. का टरसरी ट्रीटमेंट प्लांट, 15 एम.एल.डी. अल्ट्रा फिल्टरेशन तथा 5 एम.एल.डी. आर.ओ. के डेलावास व जयसिंहपुरा खोर में लगाया जाना है। इस योजना से शोधित जल को उद्योगों में उपयोग में लिया जा सकेगा। इससे अमूल्य भूजल को दोहन से बचाया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं पर लगभग 180 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

चारदीवारी में नई सीवरेज लाईनें-

साथियों, चारदीवारी के भीतर की सीवरेज लाईनें काफी पुरानी हो गई हैं। चारदीवारी में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व को देखते हुए वर्तमान सीवरेज लाईनें छोटी पड़ने लगी हैं। ऐसे में आये दिन सीवरेज लाईनें जाम होने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिये सम्पूर्ण चारदीवारी क्षेत्र में नई सीवरेज लाईनें डालने जाने की 300 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवायी जानी प्रस्तावित है।

इसी प्रकार शहर के वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिये 200 करोड़ रुपये की परियोजना बनायी गयी है। उक्त योजना भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही क्रियान्वित हो सकेगी।

वर्ष 2010–11 के बजट में शहर में सीवरेज परियोजनाओं के लिये 1000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

विरासत संरक्षण

प्रदेश के माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल की पहल पर शहर की चारदीवारी के भीतर स्थित ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिये 28.96 करोड़ रुपए की रिवाइटलाइजेशन योजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत आमेर रोड, बड़ी चौपड़, अजमेरी गेट में विभिन्न रिवाइटलाइजेशन के कार्यों के तहत सड़कों का विकास, बरामदों का जीर्णोद्धार, फसाड सुधार, गुलाबीकरण का कार्य किया जायेगा। फसाड सुधार कार्य के तहत भवनों का निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। वर्तमान में योजना के तहत चारदीवारी के भीतर बेतरतीब फैले बिजली के तारों एवं पोलों को हटाने का कार्य किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार की प्रवर्तित योजना जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन के तहत वार्ड 58 (पुराने) में 11.60 करोड़ रुपए के कार्य करवाये जा रहे हैं। रिवाइटलाइजेशन योजना के तहत 4.31 करोड़ रुपये की लागत से पन्ना मीणा बावड़ी (आमेर) का जीर्णोद्धार रखरखाव के कार्य प्रगति पर हैं।

आवारा पशु

आवारा पशु भी एक जीवन्त समस्या के रूप में है। ग्रामीण क्षेत्रों से नाकारा पशुओं को जयपुर शहर की ओर छोड़ देने से यह समस्या अनेक बार गम्भीर रूप ले लेती है। जयपुर नगर निगम द्वारा ऐसे गौवंश को हिंगोनिया गौशाला में व्यवस्थित रूप से रखे जाने का प्रावधान किया

गया है। शहर के बढ़ते आकार को देखते हुए आवारा पशु पकड़ने के लिये 10 बड़े वाहन व 4 छोटे वाहन क्रय किये जाने प्रस्तावित हैं।

आपातकालीन सेवा—109

शहर में मूक पशुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनकी समय पर सार संभाल नहीं होने पर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। आये दिन शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु गड्ढे, कुओं में गिरते रहते हैं। ऐसे पशुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके इसके लिये वर्तमान में निगम के पास कोई साधन नहीं है।

जयपुर नगर निगम आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली 108 की तर्ज पर शहर में दो वाहनों के माध्यम से 109 सेवा की निःशुल्क शुरूआत करना प्रस्तावित है। योजना में दान दाताओं को भी सहभागी बनाया जायेगा।

नवीन कारकस प्लांट की स्थापना

शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए शहर के दक्षिण छोर पर एक और अति आधुनिक कारकस प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में चैनपुरा में कार्यरत प्लांट की अधिकतम क्षमता 75 मृत पशुओं का निस्तारण है। शहर की बढ़ती दूरियों के कारण शहर में एक और प्लांट लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्लांट लगाये जाने के लिये भूमि का शीघ्र ही चिन्हीकरण कर बी.ओ.टी.पद्धति पर प्लांट लगाया जायेगा।

स्लॉटर हाऊस

वर्तमान में चैनपुरा में पाड़ा हलाली एवं बकरा हलाली स्लॉटर हाऊस पारम्परिक तरीके से चल रहे हैं। परम्परागत तरीके से पशु स्लॉटरिंग की गति काफी धीमी एवं अस्वास्थ्यकर है। इसलिए निगम द्वारा चैनपुरा में ही अति आधुनिक स्लॉटर हाऊस लगाने की योजना बनाई गई है योजना की डी.पी.आर. तैयार कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवायी जा रही है।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण सुधार

मित्रों, पर्यावरण सुधार हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शहर में बढ़ती आबादी एवं यातायात के साधनों में निरन्तर बढ़ोतारी से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। राज्य सरकार ने इस ओर कारगर प्रयास किये हैं एवं प्रदेश में “हरित राजस्थान” योजना का शुभारम्भ किया है।

जयपुर नगर निगम ने शहर में अब तक 600 से अधिक उद्यान विकसित किये हैं।

इसी प्रकार 129 उद्यान जयपुर विकास प्राधिकरण ने विकसित कर जयपुर नगर निगम को सौंपे हैं। वर्ष 2010–11 में शहर में 100 नये उद्यान विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त पुराने उद्यानों का नये सिरे से सौन्दर्यकरण किया जाना भी प्रस्तावित है।

इस कड़ी में प्रथम चरण में जयनिवास उद्यान, पौण्ड्रिक उद्यान का सौन्दर्यकरण किया जाना है।

मित्रों, शहर में निर्माणाधीन उद्यानों में विकास की दर तेजी से बढ़ाई जानी है। वर्तमान में मानसरोवर क्षेत्र में स्टोन पार्क के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का कार्य शेष है। योजनानुसार स्टोन पार्क में पत्थर की सभी किरमें एवं जानकारी एक स्थान पर प्रदर्शित की जायेंगी। भविष्य में शहर में बनाये जाने वाले सभी उद्यान विशेष थीम पर आधारित होंगे।

शहर के सभी पार्कों में पार्कों के आकार के अनुसार बच्चों के लिये नये खेल उपकरण बी.ओ.टी. आधार पर लगाये जाने प्रस्तावित हैं हैं। शहर के सभी उद्यानों में आवश्यकतानुसार लोगों को बैठने के लिए शेड बनाये जा रहे हैं एवं बैन्चें लगाई जा रही हैं।

सुचर कोना योजना

शहर की चारदीवारी में जहां उद्यानों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है वहां स्थित चौकों, चौराहों आदि पर “सुन्दर कोना” योजना के तहत उपलब्ध स्थानों में बड़े गमलों में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस कार्य से शहर के प्रमुख औद्योगिक घरानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को सहभागिता के रूप में जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है। जिससे एक ओर शहर के व्यवस्तातम इलाकों में वहां के नागरिक हरियाली के मध्य दो क्षण सुकून के जी सकेंगे। वहीं दूसरी ओर जन-सहभागिता से किये जाने वाले कार्यों में आम नागरिकों को भागीदारी प्राप्त हो सकेगी।

साथियों, जयपुर नगर निगम ने शहर में दस ऐतिहासिक बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया है। वहां पर निगम द्वारा उद्यानों को विकसित भी किया गया है। यहां स्थित उद्यानों में स्थूजिकल फाउंटेन एवं आकर्षक लाइटिंग की जानी प्रस्तावित है।

जन-सहभागिता से उद्यान विकास

वर्तमान में शहर में उद्यान रखरखाव मद पर एक बड़ी राशि व्यय की जाती है। इस व्यय में कमी के लिए आवश्यक है कि जयपुर नगर निगम जन-सहभागिता से उद्यानों का विकास एवं रख-रखाव करवाये एवं विकसित उद्यानों को क्षेत्रीय विकास समितियों को रख-रखाव के लिए दे। इस सम्बन्ध में व्यापक योजना तैयार की जा रही है। शहर में जन-सहभागिता के आधार पर दो उद्यानों में खेल उपकरण मिनी ट्रेन एवं मैरी गो राउण्ड का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार शहर के अन्य बड़े उद्यानों में भी आधुनिक खेल उपकरण लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 2200 लाख रुपए व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जयपुर समारोह

जयपुर नगर निगम के कार्यों में शहर की विरासत संरक्षण के साथ-साथ शहर की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना भी है। प्रदेश की राज्य सरकार ने इस ओर पहल करते हुए शहर के पहले गार्डन थियेटर का निर्माण स्मृति वन में करवाया है। जयपुर नगर निगम जयपुर शहर की सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाये रखने के लिए निगम द्वारा प्रतिवर्ष जयपुर शहर के स्थापना दिवस पर जयपुर समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार होली, दीपावली, ईद एवं अन्य त्यौहारों के अवसर पर परम्परागत मेलों जैसे तीज व गणगौर एवं अन्य उत्सवों पर एक ओर जहां शहर में आकर्षक सजावटी विद्युत व्यवस्था की जाती है वहीं दूसरी ओर आयोजित समारोह में रथानीय एवं राष्ट्रीय कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुति दी जाती है। इसी प्रकार शहर में दशहरा, दीपावली, होली, मोहरम, बारावफात, ऊर्स व अन्य प्रमुख त्यौहारों के अवसर पर शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों में निगम द्वारा अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2010–11 के बजट में उत्सव एवं मनोरंजन मद में 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

रैन बसेरा

साथियों, जयपुर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष शीत ऋतु के दौरान शहर में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए 18 विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरे लगाये जाते हैं। इन रैन बसेरों में बेसहारा, बेघर एवं गरीब परिवार के लोग रात्रि निवास पूर्ण सुकून के साथ करते हैं। वर्तमान में जयपुर शहर में रेलवे स्टेशन एवं बांगड अस्पताल में स्थाई रैन बसेरों का संचालन भी निगम द्वारा किया जा रहा है। जयपुर शहर में सांगानेर, आमेर में दो स्थानों पर स्थाई रैन बसेरे बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त रैन बसेरों का निर्माण एवं संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। जयपुर नगर निगम द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में जयपुर जिले की सामाजिक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

महापौर सहायता कोष

साथियों, मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से हर वर्ष बेसहारा गरीब लोगों को इलाज एवं अन्य आकर्षिक विपदाओं में सहयोग दिया जाता है। इसी तर्ज पर जयपुर नगर निगम में भी महापौर सहायता कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। कोष में दान देने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार आयकर में छूट देय होगी। कोष के संचालन के लिये जयपुर नगर निगम की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी। महापौर सहायता कोष के माध्यम से गरीब, बेसहारा लोगों के इलाज के लिये जहां एक ओर सहायता उपलब्ध कराई जायेगी वहीं दूसरी ओर प्रतिभाशाली छात्रों, खिलाड़ियों को भी सहायता दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा। कोष में दान देने वाले दानदाताओं को निगम द्वारा समय—समय पर सम्मानित भी किया जायेगा।

हैल्पलाईन सेन्टर

मित्रों, मेरी प्रथम प्राथमिकता आम आदमी की समस्याओं का प्रभावी ढंग से निस्तारण करना है। इसके लिए निगम की हैल्पलाईन सेन्टर को और अधिक कारगार बनाया जा रहा है। हैल्पलाईन सेन्टर में आने वाली शिकायत का 24 घण्टे में त्वरित गति से निस्तारण हो सके, इसके लिए एक आयुक्त स्तर का अधिकारी हैल्पलाईन सेन्टरों पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा के लिए लगाया जा रहा है। साथ ही हैल्पलाईन सेन्टरों पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ़ी दूरभाष सुविधा भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

साथियों, जयपुर नगर निगम द्वारा शहर में दैनिक रूप से सार्वजनिक विधुत, सफाई, सीवर, आवारा पशु, मृत पशु, मृत पशु अतिक्रमणों एवं अन्य निगम से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण हैल्पलाईन सेन्टर से किया जाता है। शहर में हर जोनल कार्यालय में एवं मुख्यालय पर शिकायतों के निस्तारण के लिए हैल्पलाईन सेन्टर खुले हुये हैं। निगम द्वारा सभी हैल्पलाईन सेन्टरों को वार्ड कार्यालय से जोड़ने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है। इससे वार्ड कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों की स्थिति का पता वार्ड कार्यालय स्तर पर ही पता चल सकेगी।

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। हम जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं। जयपुर नगर निगम में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जावें, इसके लिए एक आई.टी. सैल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जिससे ऑन लाईन सूचना तंत्र कायम किया जा सकें एवं आम नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण ऑन लाईन ही हो सकें एवं निगम से जुड़े करों का भुगतान ऑन लाईन किया जा सकें।

विकास कार्य

मित्रों, जयपुर शहर के विकास में सभी सभासदों एवं जनप्रतिनिधियों की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे में प्रत्येक वार्ड क्षेत्र के विकास कार्यों का दायित्व सम्बन्धित सभासद/जन प्रतिनिधियों का है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में नवनिर्वाचित बोर्ड के सभी सभासदों को 15–15 लाख रु. के विकास

कार्य करवाने का अधिकार पूर्व में दिया गया था। वर्ष 2010–11 में सभी सभासद गण उपलब्ध संसाधनों को देखते हुयेलाख रु. के विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष करवा सकेंगे।

आवास योजना

जयपुर नगर निगम द्वारा कालवाड रोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर 25 बीघा जमीन में बहुमंजिला आवास बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के एक भाग में डूब एवं जोखिम के स्थानों पर बसे कच्ची बस्ती वासियों का पुनर्वास भी किया जायेगा।

निगम कर्मियों को आवास

जयपुर नगर निगम में कार्यरत निगम कर्मचारियों की लम्बे समय से मांग थी कि उन्हें सरती दरों पर आवास उपलब्ध करवाये जाये। निगम द्वारा पूर्व में भी गोलीमार गार्डन में कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाये गये थे। परन्तु सीमित स्थान होने के कारण सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं करवाये जा सके थे। शेष रहे कर्मचारियों श्री सुन्दरसिंह भण्डारी नगर की सी-ब्लॉक में बहुमंजिले आवास बनाकर दिये जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 33907.95 लाख रु. व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

कच्ची बस्तियों का पुनर्वास एवं विकास

कच्ची बस्तियां जयपुर शहर के विकास एवं औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है। राज्य सरकार की नीतियों ने कच्ची बस्तियों के निवासियों के कल्याण के लिये अगस्त 2009 तक बसे नागरिकों का पट्टा देने का निर्णय लिया है।

जयपुर नगर निगम द्वारा इस ओर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। डूब एवं जोखिम वाले स्थानों पर बसी कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त शेष कच्ची बस्तियों के वासियों को पट्टे दिये जावेंगे। डूब एवं जोखिम वाले स्थानों पर बसी कच्ची बस्तियों के वांशिदा का पुनर्वास किया जायेगा।

शहर की कच्ची बस्तियों में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, सीवर लाईनें, सड़क व पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

वर्ष 2010–11 के बजट में इस मद में 312.93 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक स्थिति

मित्रों, नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमें 425 करोड़ के कुल बकाया दायित्व विरासत में मिले हैं। इसका मुख्य कारण पूर्ववर्ती बोर्ड के शासन में खजाने में राशियां न होते हुये भी अत्यधिक स्वीकृतियां जारी कर देना है। इसका परिणाम यह हुआ कि विकास कार्य वास्तविक रूप से क्रियान्वित न होकर केवल एक छलावा मात्र बनकर रह गये। वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 की स्वीकृतियों में से 1030 ऐसे कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं, जिनकी कुल स्वीकृति राशि 100 करोड़ रु. है और इन कार्यों पर आज दिन तक कोई भी व्यय नहीं हुआ है। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि ऐसे कार्यों की समीक्षा कर हमने अनावश्यक कार्यों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया है।

मैं आपके ध्यान में डालना चाहूँगी कि पूर्ववर्ती शासन द्वारा 75 करोड़ रु. का ऋण लिया गया है, जिसके पेटे लगभग 6 करोड़ रु. मासिक किश्तें माह मई, 2010 से निगम को चुकानी होगी।

निगम के वर्तमान संसाधनों से आय नगण्य हो रही है। आवश्यक है कि हम अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और आय में वृद्धि करें। इसी क्रम में शहर के विभिन्न वार्डों, उद्यान, गौशाला आदि से अस्थायी कर्मचारियों को हटाकर 27 लाख रु. की मासिक बचत की गई है। इसी प्रकार किराये के वाहनों में भी कटौती की गई है। नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अनुपयोगी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य मुक्त कर उनके पैतृक विभाग में भिजवाया गया है एवं कार्यों में मितव्ययता बरती जा रही है।

राजस्व स्त्रोतों से आय

(1) होर्डिंग्स :-

जयपुर शहर के वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में परिवर्तित होते स्वरूप को देखते हुये शहर में नित नये औद्योगिक, वाणिज्य घराने, मल्टीनेशनल कम्पनियां आ रही हैं। ऐसे में शहर में अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं। हमने विज्ञापनदाताओं की इस नब्ज को पहचाना है एवं शहर के हैरीटेज के अनुरूप शहर के व्यावसायिक भवनों पर लगे बेतरतीब विज्ञापनों पर रोक लगाते हुये शहर की चारदीवारी के बाहर एक रूपता के विज्ञापन पट्ट लगावाये हैं। अनावश्यक खर्चों में कटौती को ध्यान में रखते हुये एवं वसूली शत प्रतिशत हो सके इसके लिए व्यवयायिक/संस्थाओं/बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसरों पर होने वाले विज्ञापनों की वसूली वर्ष 2010–11 के लिए ठेके पर दी गई है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय से तिगुनी राशि है। इस व्यवस्था से जहां एक ओर अधिक वसूली हो रही है वही दूसरी ओर व्यवस्था में लगे स्टाफ की बचत हो सकेगी। उक्त स्टाफ से राजस्व वसूली के अन्य कार्य करवाये जायेंगे।

(2) पुलिस छतरियों एवं यातायात बूथों की नीलामी :-

निगम द्वारा वर्ष 2010–11 से यातायात नियंत्रण के लिए बनाई गई पुलिस छतरियों एवं सहायता बूथों को बी.ओ.टी. आधार पर एकरूपता से बनाया जाकर व्यवसायिक विज्ञापनों, जनजागृति यातायात स्लोगनों का प्रावधान किया है। इससे निगम को 1 करोड़ रु. की सालाना आय प्राप्त होगी।

(3) पुलिस बेरीकेट :-

शहर में यातायात व्यवस्था के लिए लगाये जाने वाले 1000 पुलिस बेरीकेट भी बी.ओ.टी. आधार पर बनाये जा रहे हैं। इनसे भी निगम को पर्याप्त आय प्राप्त होगी।

(4) चौराहे, तिराहों, डिवाईडरों का विकास :-

शहर के चौराहे, तिराहों व डिवाईडरों का निजी संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता योजना के तहत विकास करवाया जायेगा। इससे निगम द्वारा संधारण मद में व्यय किये जा रहे राशि की बचत होगी।

शहर के प्रमुख मार्गों/फुट-ब्रिज/सुलभ शैचालयों आदि का सौन्दर्यकरण एवं रख रखाव भी बी.ओ.टी. आधार पर ही करवाया जाना प्रस्तावित है।

(5) यूनीपोल बस शैल्टर :-

शहर के सौन्दर्यकरण को ध्यान में रखकर बनाये गये आधुनिक तकनीक आधारित फुट-ब्रिज, ओवर हैड साईनेज बस शैल्टरों से विज्ञापन प्रदर्शन जरीये नीलामी चालू वित्तीय वर्ष में

16 करोड की आय हुई है। वर्ष 2010–11 में इस मद में 20 करोड रु. की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

नगरीय विकास कर/गृहकर

वर्ष 2009–2010 में जयपुर शहर में नगरीय विकास कर परिधि में कुल 1 लाख 18 हजार 425 भवन आते हैं। इन सभी का कर निर्धारण करवा कर भवन स्वामियों को बिल वितरण करवाये गये हैं। जिन भवन स्वामियों पर 5000 की राशि से अधिक बकाया कर है उन्हें डिमाण्ड नोटिस तामिल करवाये गये। परिणाम स्वरूप जहाँ वर्ष 2008–09 में नगरीय विकास कर की वसूली 10.32 करोड थी वर्ष 2009–2010 को 20 करोड रु. के लक्ष्य के विरुद्ध माह फरवरी 2010 तक 11.50 करोड रु. की वसूली की जा चुकी है। माह मार्च तक लक्ष्यों के प्राप्त किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। नगरीय विकास कर सरलीकरण हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये है। जिसके अन्तर्गत टेकिनिकल एज्यूकेशन वाली निजी शिक्षण संस्थानों से आवासीय दर का दो गुणा नगरीय विकास कर वसूली एवं इसके अतिरिक्त सभी निजी शिक्षण संस्थाओं से आवासीय दर से वसूले जाने एवं मैरिज गार्डनों से आवासीय दर का डेढ गुणा वसूली के प्रस्ताव भेजे गये हैं।

भूमि की नीलामी

निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए त्वरित निर्णय लेने के लिए भूमि नीलामी सम्बन्धी कार्य को जोन से हटाकर मुख्यालय स्तर पर भू राजस्व शाखा के नाम से पुर्नगठित किया गया है। इसके लिए एक राजस्व अधिकारी व दो तहसीलदार लगाये गये हैं। राजस्व अधिकारी भूमि की नीलामी का कार्य सम्पादित कर रहे हैं तथा तहसीलदार निगम क्षेत्र में निगम की भूमि को राजस्व रिकार्ड के आधार पर चिन्हित कर इनके कब्जे लेने सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। गतवर्ष भूमि विक्रय से नगण्य वसूली की तुलना में वर्ष 2009–10 में पिछले दो माह में लगभग 5 करोड रु. की भूमि विक्रय की जा चुकी है। मार्च माह में लगभग 10 करोड रु. की भूमि विक्रय हेतु नीलामी प्रोग्राम रखा जा रहा है। निगम क्षेत्र में स्थित निगम की योजनाओं जैसे आरपीए रोड, अम्बाबाड़ी शोपिंग सेंटर, सुन्दरसिंह भण्डारी नगर, ठाठर योजना इत्यादि में कुछ भूखण्डों को कलब करके बड़े भूखण्ड के रूप में बेचा जाना प्रस्तावित है। इस योजना से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर पटेल नगर, सिवार योजना, अम्बाबाड़ी–मेघधन शोपिंग सेन्टर के पास वाली भूमि पर तथा जयसिंहपुरा खोर, जामडोली, कंवर नगर में नालों पर लगभग 150 दुकानें बनाये जाने की योजना है। इससे जहाँ एक ओर गन्दगी से निजात मिलेगी वहीं दूसरी ओर लगभग 50 करोड की अनुमानित आय होगी। राजस्थान आवासन मण्डल की जो योजनाएँ निगम को ट्रांसफर की जाती हैं, वह केवल संधारण हेतु दी जाती है, जबकि इसमें पार्कों, रोड, सीवर, स्ट्रीट लाईट, सफाई आदि के विकास व संधारण कार्य निगम द्वारा किये जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में खाली भूखण्डों को रिजर्व प्राईज पर निगम को हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जा रहा है।

जयपुर नगर निगम का वर्ष 2010–11 का प्रस्तावित बजट आपके सम्मुख विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(राशि लाखों में)

प्रस्तावित आय	राशि	प्रस्तावित व्यय	राशि
आवर्तक आय	35011.37	आवर्तक व्यय	26229.40
अनावर्तक आय	32040.03	अनावर्तक व्यय	39832.95
प्रारम्भिक शेष	2385.50	न्यूनतम अन्तिम शेष	3374.54
योग	69436.89	योग	69436.89

प्रस्तावित आगामी वर्ष 2010–11 के बजट में चुंगीकर के पेटे पुर्नभरण राशि रु. 15628.35 लाख रुपए, गृहकर से 5000.00 लाख रुपए, नगरीय विकास कर से 6000.00 लाख रुपए प्राप्त

होने की संभावना है। उपविधियों एवं अन्य एकट से 6605.00 लाख रुपए, सम्पत्ति एवं अधिकारों से 426.00 लाख रुपए, संस्थाओं से 1.01 लाख रुपए, शास्त्रियों से 100.00 लाख रुपए तथा अन्य विविध मदों से 1251.01 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बेची जाने वाली भूमि से प्राप्त 15 प्रतिशत राजस्व हिस्से के रूप में 5000.00 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। नगर निगम की भूमि एवं सम्पत्ति विक्रय से 10000.00 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है तथा अन्य स्रोतों से 2090.00 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

आगामी वर्ष 2010–11 के व्ययक अनुमानों में सामान्य प्रशासन पर 2991.95 लाख रुपए, कर वसूली पर व्यय 1017.91 लाख रुपए, जन–स्वास्थ्य पर 15808.44 लाख रुपए, सार्वजनिक रक्षा पर व्यय 333.83 लाख रुपए, रोशनी पर 3582.81 लाख रुपए, शिक्षा पर व्यय 30.08 लाख रुपए, ऋण तथा व्या भुगतानों पर 510.00 लाख रुपए, नवीन सम्पत्ति क्रय पर 2890.00 लाख रुपए तथा विविध व्यय पर 2525.00 लाख रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। नगर निगम की निधि से विकास कार्यों के लिए 12820.00 लाख रुपए का व्यय तथा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान राशि पर रुपए 21087.95 लाख रुपए के विकास कार्यों के लिए अनुमानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में बजट में विकास कार्यों पर 33907.95 लाख रुपए व्यय किये जायेंगे। इनमें से 12820.00 लाख रुपए निगम आय से एवं 21087.95 लाख रुपए अनुदान प्राप्ति से पूरे किये जायेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में सीवर लाईन डालने पर 1000.00 लाख रुपए व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। कच्ची बस्ती में विभिन्न विकास कार्यों पर 312.93 लाख रुपए व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। जिसमें 300.00 लाख रुपए निगम मद से तथा 12.93 लाख रुपए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से प्राप्त होंगे।